जनता के हाथों में शक्ति

भारत में सहकारी स मतियों की त्वरित उन्नति और उनमें हो रहे बदलाव

25 जुलाई, 2025

"भारत के लए, सहकारी स मतियाँ संस्कृति का आधार हैं, जीवन शैली हैं। भारत अपनी भावी प्रगति में सहकारी स मतियों की बड़ी भू मका देखता है।"
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

मुख्य बिंदु
• भारत में **30** क्षेत्रों में **8.44** लाख से अ धक सहकारी स मतियाँ हैं, जो ग्रामीण ऋण, रोज़गार और आ र्थक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही हैं।
• सहकारी स मतियों को कुशल, डजिटल और आपदा-प्रतिरोधी स मतियों में बदलने के लए 22 जुलाई, 2025 तक **73,492** प्राथ मक कृ ष ऋण स मतियों **(**पीएसीएस) के कम्प्यूटरीकरण के प्रस्तावों को मंज़ूरी दी गई है और **59,920** पीएसीएस को एकीकृत ईआरपी प्लेटफ़ॉर्म पर जोड़ा गया है।
• एक ही प्लेटफ़ॉर्म से व वध ग्रामीण सेवाएँ प्रदान करने के लए 22 जुलाई, 2025 तक **23,173** नई बहुउद्देशीय पीएसीएस**,** डेयरी और मत्स्य सहकारी स मतियाँ पंजीकृत की गई हैं।
• जेम पर, **667** सहकारी स मतियों को खरीदार के रूप में पंजीकृत कया गया है और 31 मार्च, 2025 तक सहकारी स मतियों द्वारा **319.02** करोड़ रुपये के **2,986** लेनदेन हुए हैं।
• राष्ट्रीय सहकारी निर्यात ल मटेड **(**एनसीईएल**)** ने **8,863** पीएसीएस **/**सहकारी स मतियों को शा मल कया है, जिनके माध्यम से **27** देशों को **5,239.5** करोड़ रुपये मूल्य की कृ ष वस्तुओं का सफलतापूर्वक निर्यात कया गया है।

भारत अपनी सहकारिता की संस्कृति के पुनरुत्थान का साक्षी बन रहा है, जिसमें जमीनी स्तर की स मतियाँ सामाजिक-आ र्थक सशक्तिकरण और समावेशी वकास के शक्तिशाली इंजन के रूप में उभर रही हैं। भारत में सहकारी स मतियों की

परिवर्तनकारी शक्ति का उल्लेखनीय उदाहरण राजस्थान की बोरखेड़ा ग्राम सेवा सहकारी स मति है। वर्ष **1954** में केवल 15 सदस्यों और मात्र 30 रुपये के शेयर के साथ स्था पत यह स मति आज **8,299** से अ धक सदस्यों और **107.54** लाख रुपये के शेयर के साथ एक संपन्न स मति के रूप में वक सत हो चुकी है - जिनमें से **70** प्रतिशत से अ धक हा शए के समुदायों से हैं। बीते दशकों में यह कृ ष के मूलभूत स्वरूप से आगे बढ़ते हुए काफी वक सत हो चुकी है। अब यह तीन शाखाओं के साथ एक मनी बैंक का संचालन करती है और अकेले **2018-19** में इसने **4.55** करोड़ रुपये की जमा रा श जुटाई। इसका ई- मत्र प्लस सेंटर बीमा और आधार- लंक्ड सु वधाओं से लेकर जाति और आय प्रमाण पत्र और उपयो गता बिल भुगतान तक की महत्वपूर्ण नागरिक सेवाएँ प्रदान करता है। इस सहकारी स मति को एनसीडीसी राष्ट्रीय सहकारी उत्कृष्टता पुरस्कार (**2010**) और एनसीडीसी क्षेत्रीय पुरस्कार (**2018**) से सम्मानित कया जा चुका है। यह बदलाव कोई अकेला मामला नहीं है—बल्कि यह सहकारी क्षेत्र को पुनर्जी वत करने की एक राष्ट्रव्यापी मुहिम का हिस्सा है।

वर्तमान में, भारत में 8.44 लाख से अ धक सहकारी स मतियां हैं, जो ऋण, आवास, वपणन, डेयरी, मत्स्य पालन आदि सहित 30 क्षेत्रों में फैली हैं - और ग्रामीण ऋण, स्वरोजगार और सामूहिक आ र्थक मजबूती की दिशा में आवश्यक साधन के तौर पर कार्य कर रही हैं।

भारत में सहकारी स मतियों की त्वरित उन्नति

8.44 लाख सहकारी स मतियां	30 क्षेत्र
73,492 पीएसीएस के कम्प्यूटरीकरण के प्रस्ताव	जेम पर 667 सहकारी स मतियाँ खरीदार के रूप में पंजीकृत
59,920 पीएसीएस को एकीकृत ईआरपी प्लेटफ़ॉर्म पर जोड़ा गया	जेम पर सहकारी स मतियों द्वारा 319.02 करोड़ रुपये के 2,986 लेनदेन
23,173 नई बहुउद्देशीय पीएसीएस, सहकारी स मतियाँ पंजीकृत	एनसीईएल ने 8,863 पीएसीएस सहकारी स मतियों को शा मल कया है/, 27 देशों को 5,239.5 करोड़ रुपये मूल्य की कृ ष वस्तुओं का सफल निर्यात कया है

स्रोत – सहकारिता मंत्रालय

और तो और वकास की इस गति की छाप गुजरात के बच्चों में भी स्पष्ट रूप से ष्टिगोचर हो रही है। साबरकांठा की बाल गोपाल बचत एवं ऋण सहकारी स मति, भारत की एकमात्र ऐसी सहकारी स मति है, जो वशेष रूप से 0-18 वर्ष की आयु के बच्चों के लए है। इस अनूठे “बाल बचत संस्कार” मॉडल के माध्यम से, बच्चों को से वंग बॉक्स दिए जाते हैं और उनमें जमा हुई रा श हर महीने उनके बैंक खातों में 6 प्रतिशत वा र्षक ब्याज पर जमा की जाती है। मार्च 2024 तक, 335 गाँवों के 19,020 बाल सदस्यों ने 17.47 करोड़ रुपये की बचत की है। यह सहकारी स मति सदस्य बच्चे के अ भभावक को स्व-गारंटीकृत ऋण और बच्चे की उच्च शक्षा के लए संप त पर ऋण भी प्रदान करती है। कुल 1,070 बच्चों के अ भभावकों को ऋण दिए गए हैं और कुल 5,370 बच्चों को वत्तीय परामर्श दिया गया है।

परिवर्तन की यह लहर **2021** में सहकारिता मंत्रालय की स्थापना के साथ शुरू हुई। मात्र चार वर्षों में, इसने सहकारी स मतियों का आधुनिकीकरण, डजिटलीकरण करने और उनमें व वधता लाने के लए **61** सु वचारित पहल शुरू की हैं। सबसे परिवर्तनकारी पहलों में **73,492** प्राथ मक कृ ष ऋण स मतियों **(**पीएसीएस**)** के कम्प्यूटरीकरण के प्रस्ताव को मंज़ूरी**, 59,920** पीएसीएस को (22 जुलाई, 2025 तक) एकीकृत उद्यम संसाधन नियोजन **(**ईआरपी) प्लेटफ़ॉर्म से जोड़ना और नए उप-नियमों के तहत बहुउद्देशीय सहकारी मॉडलों की औपचारिक शुरुआत शा मल है।

त मलनाडु के वल्लुपुरम जिले में, अरकंदनल्लूर पीएसीएस डजिटल तैयारी का एक सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करती है। जब वनाशकारी बाढ़ ने इसके भौतिक ढाँचे और कागजी दस्तावेजों को नष्ट कर दिया, तो स मति द्वारा पीएसीएस कम्प्यूटरीकरण और क्लाउड**-**बेस्ड स्टोरेज को पहले से अपना लए जाने की बदौलत शीघ्रता से पुनर्निर्माण संभव हो सका। कर्मचारियों ने सदस्यों और लेन-देन के डेटा को दूरस्थ रूप से एक्सेस कया, और न्यूनतम व्यवधान के बाद सेवाएँ शीघ्रता से फर से शुरू हो गईं। तभी से यह मामला आपदा-प्रतिरोधी सहकारी डज़ाइन का एक आदर्श बन गया है। इसी से मलता-जुलता मामला महाराष्ट्र की खरसाई व वध कार्यकारी सोसाइटी का भी है। पहले की अकुशलताओं और कागजी लेखांकन के बोझ तले दबी, इस स मति ने पीएसीएस कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम के तहत पूर्ण रूप से ईआरपी सस्टम को अपना लया। तब से, इसके प्रदर्शन में सटीकता**,** पारद र्शता**,** गति और सदस्यों की संतुष्टि—सभी मानदंडों पर सुधार हुआ है। अब यह इस बात का एक आदर्श उदाहरण है क डजिटल युग में सहकारी स मतियाँ कैसे फल-फूल सकती हैं।

सरकार की रणनीति में बड़े पैमाने का वस्तार भी शा मल है। **22** जुलाई**, 2025** तक**, 23,173** नई बहुउद्देशीय पीएसीएस**,** डेयरी और मत्स्य पालन सहकारी स मतियाँ पंजीकृत हो चुकी हैं।

इन पीएसीएस को एकल ईआरपी-आधारित डजिटल आ र्कटेक्चर के आधार पर अनाज भंडारण, उर्वरक और बीज वतरण, एलपीजी और पेट्रोल पंप, और जन औष ध केंद्रों को संभालने के लए डज़ाइन कया जा रहा है।

 वज़न स्पष्ट है: प्रत्येक गांव में एक सहकारी स मति , जो बहु-सेवा केन्द्र के रूप में कार्य करेगी।

यह डजिटल बदलाव केवल वत्त तक ही सी मत नहीं है। **31 मार्च, 2025** तक, **667** सहकारी स मतियाँ सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जेम) पर खरीदार के रूप में पंजीकृत हो चुकी थीं । राष्ट्रीय बाज़ारों तक ग्रामीण कारीगरों की पहुँच बढ़ाने के लए इन सहकारी स मतियों को वक्रेता के रूप में भी शा मल करने के प्रयास कए जा रहे हैं। **31 मार्च, 2025** तक, इन सहकारी स मतियों द्वारा **319.02** करोड़ रुपये के **2,986** लेनदेन हो चुके थे।

 डजिटल से स्थिरता का रुख करें, तो गुजरात के खेड़ा ज़िले की ढुंडी सौर ऊर्जा उत्पादक सहकारी स मति इसका एक उल्लेखनीय उदाहरण है। टाटा कंसल्टिंग और आईडब्ल्यूएमआई के सहयोग से पंजीकृत, यह भारत की पहली सहकारी सौर ऊर्जा स मति है। 12 में से 9 कसान-सदस्यों के खेतों में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कर संचाई करने और अतिरिक्त ऊर्जा राज्य ग्रड को बेचने के लए सौर पैनल लगाए गए हैं। दो वर्षों में, उन्होंने हरित ऊर्जा के माध्यम से **8** लाख रुपये अर्जित कए हैं, जिससे डीज़ल पर निर्भरता कम हुई है और टिकाऊ कृ ष को बढ़ावा मला है।

भारत में सहकारी स मतियाँ तेज़ी से स्थानीय सामुदायिक केंद्रों के रूप में काम कर रही हैं, जो वत्तीय सेवाओं, शै क्षक वकास, कल्याणकारी योजनाओं, स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच और आवश्यक उपयो गताओं के लए एक एकीकृत मंच प्रदान करती हैं—जिससे जमीनी स्तर पर समावेशी वकास को बढ़ावा मलता है। पश्चिम बंगाल की कहानियाँ इस राष्ट्रव्यापी गति को और सु ढ़ता भी प्रदान करती हैं।

मधुसूदनकाटी कृ ष ऋण स मति (एसकेयूएस) बुनियादी कृ ष ऋण से आगे बढ़कर पूर्ण-सेवा प्रदाता बहुउद्देशीय पीएसीएस बन गई है। यह कसान क्रे डट कार्ड और स्वयं सहायता समूह ऋण प्रदान करती है, इफको और बेनफेड उत्पादों सहित उर्वरकों और कीटनाशकों के खुदरा और थोक वक्रेता के रूप में कार्य करती है। यह स मति एक कस्टम हायरिंग सेंटर, ग्रामीण जल परियोजना, कृ ष उपज खरीद केंद्र और उपभोक्ता वस्तुओं की दुकानें भी चलाती है। अपनी आ र्थक ग त व धयों के अलावा, यह स्वास्थ्य श वरों का आयोजन और एक च कत्सा केंद्र, बाल उद्यान और सामुदायिक केंद्र का संचालन करके सामाजिक कल्याण में स क्रय रूप से योगदान देती है। इसी प्रकार, मुराकाटा समाबे कृ ष उन्नयन स मति (एसकेयूएस) की शुरुआत 45 सदस्यों से हुई थी और 2022 तक यह संख्या बढ़कर **1,603** सदस्य हो गई। शुरुआत में यह एक गैर-जमा ऋण स मति के रूप में काम करती थी, अब जमा सु वधाओं सहित समग्र बैं कंग सेवाएँ प्रदान करती है। यह स मति स्थानीय कसानों को कफायती दरों पर कस्टम हायरिंग सेंटर सेवाएँ प्रदान करती है। अ धकांशतः वनाच्छादित और आ र्थक रूप से कमजोर वर्गों को कवर करते हुए यह मुख्य रूप से कृ ष-आधारित समुदाय को सेवाएं प्रदान करती है। पहले एकल फसल की खेती तक सी मत रहने वाले स्थानीय कसान अब केसीसी ऋण, फसल बीमा और कफायती कटाई सेवाओं तक व्यापक पहुंच से लाभान्वित हो रहे हैं, जिससे साल भर खेती संभव हो रही है।

जम्मू और कश्मीर के पुंछ ज़िले में, गोल्ड एमपीसीएस ल मटेड को उसकी व्यापक ग्रामीण सेवाओं के लए जाना जाता है। यह फसल ऋण, बीमा, पीएम सूर्य घर योजना की सु वधा प्रदान करती है और एक कॉमन स र्वस सेंटर (सीएससी) के रूप में कार्य करती है। वत्त वर्ष **2023-24** में, इस स मति के सीएससी ने **641** लेनदेन पूरे कए, जब क वत्त वर्ष **2024-25** (11 नवंबर, 2024 तक) में **1,852** लेनदेन दर्ज कए गए, जो इसकी बढ़ती लोक प्रयता और उपयो गता को दर्शाता है। पछले छह महीनों में, सीएससी के माध्यम से **9.16** लाख रुपये मूल्य के लेनदेन कए

गए—जिससे नागरिकों को पैन कार्ड बनवाने, बीमा और बिल भुगतान में मदद मली। इसी प्रकार, कश्तवाड़ (जम्मू और कश्मीर) में, अथोली बहुउद्देशीय सहकारी स मति स्थानीय समुदाय के लए जीवन रेखा का काम करती है। आदर्श उपनियमों के तहत संचा लत, यह स मति एक जन औष ध केंद्र चलाती है और सीएससी सेवाएँ प्रदान करती है और आंगनवाड़ी केंद्रों को पोषण संबंधी आपूर्ति प्रदान करती है। वत्त वर्ष **2024-25** में इसका कारोबार **18.66** लाख रुपये था, जो समाज में इसकी बढ़ती व्यावसायिक सफलता और प्रभाव को दर्शाता है।

भारत के सहकारी सुधारों ने राष्ट्रीय स्तर पर भी आकार लया है। सहकारी स मतियों को बाज़ारों तक पहुँच, ब्रां डंग और निर्यात क्षमता प्रदान करने के लए **2023** में, तीन बहु-राज्य सहकारी स मतियों का गठन कया गया:

- राष्ट्रीय सहकारी निर्यात ल मटेड (एनसीईएल)
- राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स ल मटेड (एनसीओएल)
- भारतीय बीज सहकारी स मति ल मटेड (बीबीएसएसएल)

31 मार्च **2025** तक, एनसीईएल ने सामूहिक निर्यात की सु वधा के लए पहले ही **8,863** पीएसीएस/सहकारी स मतियों को शा मल कर लया है। इसके अलावा, एनसीईएल ने चावल, गेहूं, मक्का, चीनी, प्याज और जीरा सहित लगभग **13.08** एलएमटी कृ ष वस्तुओं का सफलतापूर्वक निर्यात कया है, जिनका मूल्य **27** देशों में **5,239.5** करोड़ रुपये है। यद्य प 5,185 पीएसीएस/सहकारी स मतियां एनसीओएल की सदस्य बन गई हैं। एनसीओएल ने 'भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड' के तहत लगभग **167.1** लाख रुपये के **21** उत्पाद लॉन्च कए हैं। एनसीओएल ने **10** राज्यों में नोडल एजें सयों के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर भी हस्ताक्षर कए हैं। दूसरी ओर, **19,171** पीएसीएस/सहकारी स मतियां बीबीएसएसएल की सदस्य बन गई हैं। बीबीएसएसएल को **13** राज्यों में बीज लाइसेंस प्रदान कया गया है।

मंत्रालय ने इस परिवर्तन को और तेज़ करने के लए हाल ही में **24** जुलाई, **2025** को एक नई राष्ट्रीय सहकारी नीति शुरू की है। राष्ट्रीय सहकारी नीति का उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को समावेशी बनाना, उन्हें पेशेवर रूप से प्रबं धत करना, उन्हें भ वष्य के लए तैयार करना और वशेष रूप से ग्रामीण भारत में बड़े पैमाने पर रोज़गार और आजी वका के अवसर पैदा करने में सक्षम बनाना है। नई सहकारी नीति **2025-45** तक यानी अगले दो दशकों के लए भारत के सहकारी आंदोलन में एक मील का पत्थर साबित होगी। नई नीति "सहकार-से-समृद् ध" के

वज़न को प्राप्त करने का रोडमैप तैयार करेगी और 2047 तक भारत के "आत्मनिर्भर" और " वक सत" बनने की सामूहिक महत्वाकांक्षा में योगदान देगी।

नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति

नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति का उद्देश्य

- "सहकार-से-समृद् ध" के वज़न को बढ़ावा देना
- ग्रामीण अर्थव्यवस्था की प्रगति की रफ्तार में तेजी लाना
- रोज़गार के अवसरों का बड़े पैमाने पर सृजन करना
- देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूती प्रदान करना
- सहकारिता क्षेत्र को अपना सामर्थ्य हा सल करने में मदद करना
- सहकारिता संस्थाओं के लए समग्र   ष्टिकोण तैयार करना
- नीतिगत, कानूनी और संस्थागत अवसंरचना तैयार करना
- सहकारिता आधारित वकास मॉडल को बढ़ावा देना

स्रोत : सहकारिता मंत्रालय

इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा घो षत अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के तहत सहकारिता मंत्रालय ने भारतीय सहकारी स मतियों को वैश्विक मंच पर स्था पत करने के लए एक व्यापक राष्ट्रीय कार्य योजना शुरू की है। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, सर्वोत्तम प्रथाओं के दस्तावेज़ीकरण और डजिटल पहुँच के माध्यम से भारत के सफल सहकारी मॉडलों—जैसे अमूल, इफको और कृभको—को प्रद र्शत करने पर ध्यान केंद्रित करती है। सरकार सहकारी निर्यात को बढ़ावा देने, सहकारी स मतियों के भीतर स्टार्टअप्स को समर्थन देने और देश-व्यापी शक्षा को सुगम बनाने के लए भी काम कर रही है। इस पहल का उद्देश्य भारत की जमीनी ताकत और वशाल सदस्यता आधार का लाभ उठाकर सहकारी नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाना है।

भारत की कुछ सफलतम सहकारी स मतियाँ

सहकारी स मतियाँ	क्षेत्र	उल्लेखनीय उपलब्धि
अमूल (जीसीएमएमएफ)	डयेरी	भारत की सबसे बड़ी डेयरी सहकारी स मति; जिसने "श्वेत क्रांति" में महत्वपूर्ण भू मका निभाई, जिससे भारत वश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बन गया; जिसका कारोबार 7.3 बि लयन से अ धक है।
इफको	उर्वरक	भारत की सबसे बड़ी उर्वरक सहकारी स मति और प्रति व्यक्ति जीडीपी के लहाज से दुनिया की सबसे बड़ी सहकारी स मति; 7.3 बि लयन (वत्त वर्ष 23) से अ धक राजस्व सहित इसकी उल्लेखनीय वृद् ध ने इसे फॉर्च्यून इं डया 500 सूची में स्थान दिलाया।
कर्नाटक दुग्ध संघ (नंदिनी)	डयेरी	भारत में दूसरी सबसे बड़ी डेयरी सहकारी स मति; कर्नाटक में 15 दुग्ध संघों के साथ काम करती है, प्राथ मक डेयरी सहकारी स मतियों से दूध खरीदती है; शहरी और ग्रामीण दोनों बाजारों में अपनी सेवाएं देती है, जिससे 1,500 से अ धक सदस्य लाभान्वित होते हैं।
इं डयन कॉफ़ी हाउस सोसाइटी	उपभोक्ता/रेस्तरां	श्र मक सहकारी स मतियों के नेटवर्क द्वारा प्रबं धत; इसके लगभग 400 कॉफी आउटलेट हैं
उरालुंगल श्रम अनुबंध सहकारी स मति	श्रम सहकारी स मति	भारत की सबसे पुरानी श्रम सहकारी स मति; लगभग 1415 व्यक्तियों की सदस्यता के साथ यूएलसीसीएस ने 7500 से अ धक

		परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा कया है

भारत में सहकारी स मतियों की त्वरित उन्नति अब कोई काल्पनिक आदर्श नहीं रह गया है—यह एक जमीनी, मूलभूत क्रांति है। सहकारी स मतियाँ न केवल लोगों को सशक्त बना रही हैं—बल्कि वे समावेशी, लोकतांत्रिक वकास की नए सरे से परिकल्पना भी कर रही हैं। एक सदी पहले एक जन आंदोलन के रूप में शुरू हुई यह मुहिम अब भारत के न्यायसंगत और समावेशी वकास की कुंजी बन सकती है।

संदर्भ

सहकारिता मंत्रालय

कुरुक्षेत्र पत्रिका : जुलाई 2025 संस्करण (पृष्ठ सं. 22)

https://cooperatives.gov.in/en
https://www.cooperation.gov.in/en/2023-2024
https://x.com/MinOfCooperatn/status/1816337535905550687
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2146772
https://www.cooperation.gov.in/en/major-initiative-of-the-ministry
https://vamnicom.gov.in/uploads/4f51e1ee3035ac8005355277540565be.pdf
https://vamnicom.gov.in/uploads/ebc76414f685d0ee399c9b8f993505d0.pdf
https://www.cooperation.gov.in/sites/default/files/2025-03/IYC%20Annual%20Action%20Plan-English.pdf

पीएम इं डया

https://www.pmindia.gov.in/en/news_updates/pm-inaugurates-ica-global-cooperative-conference-2024/

गुजरात सरकार

https://rcs.gujarat.gov.in/Home/ICASS

राजस्थान सरकार

https://rajsahakar.rajasthan.gov.in/Content/SuccessStory/Borkheda_Village_Service_Cooperative_Society_Kota.pdf

पश्चिम बंगाल सरकार

https://cooperation.wb.gov.in/assets/pdf/Madhusudankati.pdf
https://cooperation.wb.gov.in/assets/pdf/Murakata-SKUS.pdf

****

एमजी/आरपीएम/केसी/आरके/डीए